

ग्रसाबारश

### EXTRAORDINARY

भारा I-खपड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

া नई बिल्ली, গ্রুকবাर, दिसम्बर 31, 1965/पौष 10, 1887 (হাক) ১- NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 1965/PAUSA 10, 1887 (SAKA)

में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Parate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

# MINISTRY OF COMMERCE

#### RESOLUTION

#### TARIFFS

New Delhi, the 31st December, 1965.

'ar/65.—The Tariff Commission has submitted its Report on of protection to the Ball Bearings Industry and the grant 'er Roller Bearings Industry on the basis of an inquiry 'er Sections 11(e) and 13 of the Tariff Commission Act, commendations are as follows:—

nted to ball bearings and adapter ball bearings, not im, bore diameter, covered by I.C.T. Item i) and 72(37) should be continued for a further years ending 31st December, 1968 but the of duty should be raised to 125 per cent urther, ball bearings and adapter ball bearings 1 mm. bore diameter and upto and including iameter and roller bearings upto and including

- 100 mm. bore diameter (excluding railway axle box bearings) should be brought within the scheme of protection and subjected to the same rate of duty, namely, 125 per cent ad valorem. The duty also should remain in force till 31st December, 1963. An craft bearings will also be outside the scheme of protection.
- (2) If the recommendations regarding protection are accepted 1 Government, the relevant items of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 should be amended.
- (3) For the reasons mentioned by the Tariff Commission, the futur of the small scale sector of the roller bearings industry i doubtful. Such units as have made good progress may be give necessary assistance in all possible ways but great caution he to be exercised in allowing any expansion of such units.
- (4) Since the imported raw materials account for only 15 to 30 percent of the cost of the finished products, and these will progressively be available in the country, it is desirable to encourage the fullest manufacture of roller bearings by providing foreign exchange for the import of raw materials to the required externation than import of finished products.
- (5) Either the Directorate General of Technical Development or to Ministry of Steel and Mines should make an assessment of the demand for various sections of steel required for the respections industry and co-ordinate the efforts of capable production of rods, wires and tubes to ensure sufficient production the indigenous demand by the end of the Fourth Five Year-
- (6) While issuing licences for raw materials for the roller beindustry for sources other than the General Currency Atthe Dollar Area, Government should first satisfy themsel producers will be able to secure suitable raw materithese sources
- (7) Blanket licences or licences with monetary limits shorpossible contain a schedule or schedules of the spermitted to be imported and the protective rate apply uniformly no matter what the end use migh extent possible sizes near the protected type allowed to be imported except by a consumer ar a proper check on the quantities needed by him
- (8) Periodical meetings between the Ball and Roller facturers' Association, the State Trading Corporat Directorate General of Technical Development sh settling import policy which would ensure that concurrent and prospective capacity is fully entre the consumers' needs are regularly and ader
- (9) Early steps should be taken to establish research facilities in each undertaking laboratory to ensure high standards of
- (10) Government should either control the manufacturers of roller bearings or
- (11) Future imports of ball and roller beart the "Monthly Statistics of the Foreign lines indicated by the Tariff Commiss
- (12) Encouragement needs to be given for the manufacture of specialised tool ed by the roller bearings industry.

- 8. बाल तथा रोलर वयरिंग निर्माता संघ, राज्यं व्यापार निगम श्रीर तकनीकी विकास के महानिदेशक के बीच होने वाली नियतकालिक बैठकों से श्रायात नोति निर्धारित करने में सहायता मिलनी चाहिए जिससे यह सुनिष्चित हो कि उद्योग को समवर्षी तथा भावी क्षमता का पूरा उपयोग हो रहा है श्रीर उपभोक्ताश्रों की जरूरतें नियमित तथा पर्याप्त रूप से पूरी हो रही हैं।
- 9. प्रत्येक कारखाने में आधुनिक डिजाइन तैयार करने तथा गवेषणा की सुविधाएं प्रदान करने श्रीर साथ ही ऊंचे किस्म के मानक सुनिश्चित करने हेतु एक केन्द्रीय परीक्षणा प्रयोगशाला स्थापित करने के 'तये प्रारम्भिक कदम उठाये जाने चाहिए ।
- 10. सरकार को चाहिए कि या ो वह ोलर बर्यारंगों के सभी निर्माताश्चों को बिक्री कीमतों का नियंत्रएा करें, श्रन्यथा वह किसी भी निर्माता की कीमत का नियंत्रएा न करें।
- 11. बाल तथा रोलर बेर्यारगों का भावी श्रायात टैरिफ श्रायोग द्वारा बताये गये तरीके के श्रनुसार ''मन्थली स्टेटिस्टिक्स श्राफ दि फारेन ट्रेड श्राफ इण्डिया'' में दिया जाना शाहिए ।
- 12. रोलर बेयरिंग उद्योग द्वारा श्रपेक्षित विशिष्ट श्रौजारों, जिगों श्रौर फिक्सचरों का उत्पादन करने के लिये कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन देने की श्रावण्यकता है।
- 13. सभी निर्माताश्रीं द्वारा कारखाने-के-भीतर प्रशिक्षणा की सुविधाएं दी जानी चाहिएं श्रीर डिजाइन बनाने वालों तथा गवेषणा करने वालों के संवर्ग बनाने चाहिएं।
- 2. सरकार ने सिफारिश (1) और (2) पर सावधानी से विचार किया है भीर इस तथ्य को देखते हुये कि श्रायात से किसी प्रकार की श्रस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि देश में ही बनने वाले विशिष्ट बेयरिंगों के श्रायात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है और इस बात को घ्यान में रखते हुये भी कि सीमा शुल्कों की दरें विक्त (संख्या 2) श्रिधिनियम, 1965 के श्रधीन युक्तियुक्त बना लीगयी हैं, सरकार का विचार है कि बाल बयरिंग उद्योग को 31 दिसम्बर, 1965 के पश्चात् टैरिफ संरक्षण दिये रहने की श्रावश्यकता नहीं है।

गुल्क की दरों को फिलहाल जारी रखने का सरकार का विधार है। सरकार के निर्णय को कियान्त्रित करने के लिये आवश्यक विधि-व्यवस्था यथासमय की जायेगी।

- सरकार ने सिफारिश (3) स्पीर (12) नोट कर ली हैं स्पीर उनको यथासम्भव किथान्वित करने के लिये कदम उाये जायेंगे।
- 4. बाल और रोलर बयरिंग निर्माता संघ का ध्यान सिफारिश (8) की भ्रोर भ्राकृष्ट किया जाता है।

 बाल बेयरिंग तथा रोलर बेयरिंग उद्योग का ध्यान सिकारिंग (9) भ्रौर (13) की श्रोर दिलाया जाता है।

### श्चावेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और इसकी एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेज दी जाये ।

> पी० के० जे० मेनन, संयुक्त सचिव ।